

असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग 1—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

村. 251] No. 251] मई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर ९, १९९९/कार्तिक 18, १९२१

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 1999/KARTIKA 18, 1921

वाणिज्य मंत्रालय (पाटन रोधी प्रभाग) आरंभ करने की सूचना नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1999

विषय : रूस और कंजाकिस्तान मूल के या वहाँ से निर्धातित लो कार्बन फैरो क्रोम (एलसीएफसी) पर लगाए गए पाटन-रोभी शुल्क की समीक्षा का आरंभ।

सं. 44/1/99-डीजीएडी.—नम्प-निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) ने सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटन-रोधी सीमा-शुल्क की बहुचान, समाकलन और समाहरण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 का ध्यान करते हुए कस और कंजाकिस्तान मूल के या वहाँ से निर्यातित एल सी एफ सी के आयातों पर निश्चित पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

- 1. विचाराधीन उत्पादः विचाराधीन उत्पाद, जिसकी पाटन के लिए जॉच की जा रही है, लो काबर्न फैरो क्रोम (जो एल सी एफ सी के नाम से प्रसिद्ध है) है जिसमें काबन अंश 0.03% से 0.20% तक तथा क्रोमियम अंश 65% से 70% तक है। एल सी एफ सी क्रो सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची -। के सीमा-शुल्क शीर्ष 7202,49 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान समीक्षा के कार्यक्षेत्र पर बाध्य कर नहीं है।
- 2. पाटन रोधी जाँच का आरंभः सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा उसके अंतर्गत बनी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के लिए आवश्यक है कि वह सिफारिश किए गए पाटन-रोधी शुल्क लगाए रखने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करें। अतः नाम-निर्दिष्ट प्राधिकारी मानता है कि प्राधिकारी की सिफारिशों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार। अधिसूचना संठ 47/एडीडी/94, तारीख 3 दिसम्बर 1996 हम्या नाम पाटन रोधी शलक की हम अनुसरण में

- 3. अधिसूचना सं0 47/एडीडी/94 , तारीख 3 दिसम्बर् 1996 द्वारा अधिसूचित अंतिम निष्कर्षों की समीक्षा करने का निश्चय कर लेने पर प्राधिकारी एतद्द्वारा, रूस और कजाकिस्तान मूल के या वहाँ से निर्यातित एल सी एफ सी के आयातों पर सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क की पहचान, सगाकलन एवं समाहरण तथा क्षति-निर्धारण0 निथमावली, 1995 के अनुसार लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क को लगाए रखने की आवश्यकता की समीक्षा करते हुए जाँच आरंभ करता है।
- 4. इस समीक्षा में अधिसूचना सं0 47/एडीडी/94, तारीख 3 दिसम्बर, 1996 के सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा :
- 5. **जाँच की अवधि:** वर्तमान समीक्षा के प्रशाजन के लिए जाँच की अवधि 1 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 1999 तक की है।
- 6. मैं0 फैरो एलायज कारपोरेशन लि0, हिन्दुस्तान हाउस, 8वी मंजिल, 18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001 को , जिसका पंजीकृत कार्यालयः श्री राम भवन, तुमसार (महाराष्ट्र) में तथा कारजाना श्रीराम नगर, जिल-विजयनगरम, आंध्र-प्रदेश में है, उप्पर संवर्धित अधिसूचना में स्वदेशी उद्योग माना गया था । उपरोक्त अधिसूचना से संबंधित पिछली जॉच में याचिका, मैं0 फैरो एलॉय कारपोरेशन लि0 की ओर से और उनके लिए इण्डियन फैरो एलायज एसोसिएशन, मुम्बई द्वारा दायर की गई थी । प्राधिकारी पूर्वोक्त नियमावती के अनुसार उसी कम्पनी को स्वदेशी उद्योग मानने का प्रस्ताव करता है।
- 7. सूचना प्रस्तुत करना ज्ञात हितबद्ध आयातकों और निर्यातकों एवं स्वदेशी उद्योग को निर्धारित प्रपन्न और स्वरुप में संबद्ध सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से लिखा जा रहा है। वर्तमान जॉव में रुवि रखने वाली कोई अन्य पार्टी भीनिम्नलिखित को लिख सकती हैं- नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अपर सचिव.

(पाटन रोधी प्रभाग).

भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय

उद्योग भवन

नई दिल्ली - 110 011

- 8. समय सीमा वर्तमान जॉव से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में इस प्रकार भेजी जानी चाहिए ताकि वह प्राधिकारी के पास उपरोक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख़ से आंधेक-से अधिक 40 दिनों के भीतर पहुंच जाए । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो नाम-निर्दिष्ट प्राधिकारी पूर्वोक्त नियमावली के अनुसार अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलेखित कर सकता है।
- ् सार्वजनिक फाइल का निरीक्षणः नियम ६ (7) के अनुसार कोई भी हितबद्धपार्टी, अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अ-गोपनीय अंशों की सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है।

10. यदि कोई इच्छुक पार्टी उचित अविध के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुँच से इंकार करती है या उसे उपलब्ध कराने में असमर्थ रहती है या महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी,अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकार्ड कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो वह उचित समझता है।

रति विनय झा. नाम-निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

(Anti-Dumping Division)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 1999

Subject:—Initiation of review of anti-dumping duty imposed on Low Carbon I originating in or exported from Russia and Kazakhstan.

No. 44/1/99-DGAD.—The Designated Authority (hereinafter referred to a gard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification, Assess Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, recommended imposition of definitive Anti-Dumping Duty on imports of LCFC originating in or exported from Russia and Kazakhstan.

- 1. <u>Product under Consideration:</u> The product under consideration which has been investigated for dumping is Low Carbon Ferro Chrome (widely known as LCFC) having carbon content ranging between 0.03% to 0.20% and Chromium content ranging between 65% and 70%. LCFC is classified under customs heading 7202.49 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is however indicative only and is not binding on the scope of the present review.
- 2. <u>Initiation of Anti-Dumping Investigation:</u>-The Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the rules made thereunder require the Authority to review, from time to time, the need for the continued imposition of Anti-Dumping duty recommended. The Designated Authority therefore considers that the anti-dumping duty imposed by the Central Government in pursuant to the recommendations made by the Authority vide Notification No. 47/ADD/94 dated 3rd December, 1996, need to be reviewed at this stage.
- 3. Having decided to review the Final Findings notified vide Notification No. 47/ADD/94 dated 3rd December, 1996, the Authority hereby initiates investigations to review the need for continued imposition of the anti-dumping duty imposed on imports of LCFC originating in or exported from Russia and Kazakhstan in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995.

- 4. This review covers all aspects of Notification No. 47/ADD/94 dated 3rd December, 1996.
- 5. <u>Period of Investigation:</u> The period of investigation for the purpose of the present review 1st April 1998 to 31st March, 1999.
- 6. M/s Ferro Alloys Corporation Ltd., Hindustan Times House, 8th Floor 18-20 Kasturba Gandhi Marg, New-Delhi 110001, having its Registered Office at Shreeram Bhawan, Tumsar (Maharashtra) and works at Shreeramnagar, Distt. Vizianagaram, Andhra Pradesh, was considered as the domestic industry in the above referred Notification. The petition in the previous investigation leading to the above referred Notification was filed through Indian Ferro Alloys Association, Bombay for and on behalf of M/s Ferro Alloys Corporation Ltd. The Authority proposes to consider the same company as the domestic industry in accordance with the Rules supra.
- 7. <u>Submission of Information:</u>—The exporters and importers known to be concerned and domestic industry are being informed separately to enable them to file all relevant information in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:-

The Designated Authority (Anti-Dumping Division) Government of India Ministry of Commerce Udyog Bhavan, New-Delhi 110011

- 8. <u>Time Limit:</u> All information relating to this review should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.
- 9. Inspection of Public File: In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing the non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.
- 10. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority